भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3191

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन और विस्तार

3191. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में चयनित राज्यों में अटल भूजल योजना के अंतर्गत निर्माण की जा रही परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इन राज्यों में वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) भूजल पुनर्भरण, जल स्तर और स्थानीय जल संरक्षण प्रथाओं पर इस योजना का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मापनीय प्रभाव क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन राज्यों से कोई नवीन मॉडल या सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान की है जिन्हें अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का देशभर के अन्य जल-संकटग्रस्त जिलों और राज्यों में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विस्तार के लिए क्या समय-सीमा और मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): अटल भूजल योजना, भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सामुदायिक नेतृत्व वाली सहभागी भूजल प्रबंधन योजना है जिसका कार्यान्वयन 7 राज्यों के 80 पानी की कमी वाले जिलों में किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत शुरू की गई प्रमुख गतिविधियों/कार्यों विवरण निम्नानुसार है:

- सभी 7 राज्यों की सभी 8,203 अटल जल ग्राम पंचायतों (जीपी) में भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीकों से भूजल आंकड़ों का मापन और सार्वजनिक प्रकटीकरण किया गया है।
- सभी 7 राज्यों के सभी जीपी द्वारा सामुदायिक-नेतृत्व आधारित जल बजट (डब्ल्यूबी) और जल सुरक्षा योजनाएँ (डब्ल्यूएसपी) तैयार की गई हैं और प्रत्येक वर्ष अद्यतन की जाती हैं।
- ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के साथ-साथ जीपी स्तर पर 1.25 लाख से अधिक के प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।
- योजना के अंतर्गत लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पीजोमीटर, डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) और वर्षा गेज स्थापित किए गए हैं।

- 7 राज्यों में जल संरक्षण और भूजल पुर्नभरण हेतु लगभग 81,700 आपूर्ति-आधारित संरचनाओं जैसे चेक डैम, तालाब, पुनर्भरण शॉफ्ट/गड्ढे इत्यादि का निर्माण//नवीनीकरण किया गया।
- 7 राज्यों में लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि को कुशल जल-उपयोग पद्धतियों (ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, मल्चिंग, फसल विविधता आदि) के अंतर्गत लाया गया है।

(ख): अटल भूजल योजना परिणाम आधारित योजना है और विभिन्न सूचकांकों के अंतर्गत प्रतिभागी राज्यों के कार्यनिष्पादन के आधार पर निधियों का आवंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निधियां परिवर्तनीय होती हैं और निधियों का आवंटन कार्यनिष्पादन करने वाले राज्यों के स्थान पर बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाले राज्यों को अंतरित किया जा सकता है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2025 तक जारी की गई और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ग): भूजल स्तर में गिरावट पर रोक लगाना, अटल भूजल योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतकों में से एक है। इस योजना का कार्यान्वयन 7 राज्यों के 229 ब्लॉकों में किया जा रहा है और 229 ब्लॉकों में से कुल 83 ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार देखा गया है, जिसका विवरण **अनुलग्नक- II** पर दिया गया है।

अटल भूजल योजना के तहत, विभिन्न स्थानीय जल संरक्षण संरचनाओं/पद्धतियों को समुचित महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि वे पारंपरिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं और स्थानीय भूभाग और जलवायु परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। गोकते, बावड़ी, जोहड़, टंकी, कल्याणी, डिग्गी आदि जैसी पारंपरिक संरचनाओं के निर्माण की पद्धतियों को पुनर्जीवित किया गया है और इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।

(घ): अटल भूजल योजना के अंतर्गत, प्रतिभागी राज्यों ने कुछ नवोन्मेषी मॉडलों को भी अपनाया है जोकि जागरूकता निर्माण, क्षमता निर्माण और जल के कुशल उपयोग के संबंध में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। कुछ सर्वोत्तम पद्धतियों, जिनकी पहचान की गई और प्रलेखीकरण किया गया और देश के अन्य हिस्सों में दोहराये जाने और विस्तार देने हेतु सार्वजनिक किया गया, उनका विवरण निम्नानुसार है :

- गुजरात: पंचायत, तालुका और जिला स्तर पर भूजल गुणवत्ता प्रशिक्षण हेतु मोबाइल वैन का उपयोग। किसान स्थल पर परीक्षण हेतु बोरवेल के नमूने लाते हैं, जिससे तत्काल, यथोचित निर्णय लेना संभव हो पाता है।

- कर्नाटक: चिकारबल्लापुर और बेंगलूरु ग्रामीण में अंगूर, अनार और गुलाब की खेती के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित 'फसल एवं फीलियों ' पद्धति का उपयोग किया गया। ईष्टम सिंचाई हेतु ये मिट्टी के सेंसर्स, मौसम डाटा और कीट भविष्यवाणी का उपयोग करते हैं ताकि सिंचाई को इष्टतम किया जा सके, जिससे सुनिश्चित खेती के माध्यम से 20-40% पानी की बचत होती है।

- महाराष्ट्र: भूजल सूचना प्रसारण केंद्र (जीआईडीसी) का निर्माण, जो कि पंचायत स्तर का एक समुदाय-केंद्रित ज्ञान केंद्र है, जो भूजल डाटा, जल बजट और योजना अद्यतन प्रदान करता है, जिससे समुदायों को जल प्रबंधन के निर्णय लेने में मदद मिलती है।

- राजस्थान: एक संपूर्ण जल-बचत पॉली-हाउस मॉडल विकसित किया गया है जो पॉली-हाउस, खेत, तालाब, सौर पंप और सूक्ष्म-जल सिंचाई जैसी कई प्रमुख जल संरक्षण तत्वों को एकीकृत करता

है। कुशल जल उपयोग को समर्थ बनाने के अतिरिक्त, यह मॉडल वर्धित उपज, कम लागत और बेहतर आय के प्रदान करने के माध्यम से वर्ष भर उच्च मूल्य वाली फसल उत्पादन को सहयोग प्रदान करता है।

- मध्य प्रदेश: पियोजोमीटर, वर्षा गेज और पानी के प्रवाह मीटर से संबंधित तकनीकी ज्ञान को समुदाय और छात्रों के लिए सरल बनाते हुए 6 जिलों की 670 ग्राम पंचायतों को जल साक्षरता रथ अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया। डिजिटल डाटा में पारदर्शिता के साथ तकनीकी साक्षरता शामिल करते हुए इस पहल ने स्थानीय नेतृत्व को सुदृढ़ किया है और जल अभिशासन में सामुदायिक भागीदारी हेतु एक मॉडल स्थापित किया है।
- हरियाणा: राज्य ने उपग्रह, मौसम, मिट्टी और फसल डाटा के उपयोग के माध्यम से पानी के ईष्टम उपयोग हेतु आईआईएसआईएफ (सिंचाई पूर्वानुमान हेतु सिंचाई बुद्धिमता सॉफ्टवेयर) नामक नवोन्मेषी प्रणाली विकसित की है। यह उत्पादकता और स्थिरता को बढावा देने के साथ एक मोबाइल/वेब ऐप के माध्यम से कीटनाशक परामर्श, व्यक्तिगत सिंचाई को उपलब्ध कराता है।
- उत्तर प्रदेश: "अपने ग्राम पंचायत को जानें" पहल, पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी को बढावा देने के माध्यम से ग्राम पंचायतों को क्यूआर कोड प्रदान करके वास्तविक भूजल डाटा, जल बजट, मौजूदा जल संरक्षण संरचनाएँ, और जारी कार्यकलापों से संबंधित वास्तविक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है।

(ङ.): अटल भूजल योजना निर्धारित अवधि और परिव्यय वाली सहभागी भूजल प्रबंधन से संबंधित एक मात्र प्रायोगिक योजना है। वर्तमान में, इस परियोजना के प्रभावों का आकलन किया जा रहा है।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

"अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन और विस्तार" के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को लोकसभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 3191 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(राशि करोड़ रूपए में)

राज्य	**जारी की गई**	**उपयोग की गई**
गुजरात	595.57	470.61
हरियाणा	753.00	620.48
कर्नाटक	903.21	831.71
मध्य प्रदेश	211.75	193.89
महाराष्ट्र	643.82	609.59
राजस्थान	489.50	484.79
उत्तर प्रदेश	264.83	207.13
कुल	**3861.68**	**3418.20**

*****

<u>अनुलग्नक-II</u>

"अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन और विस्तार" के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को लोकसभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 3191 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य	कुल ब्लॉक	भूजल स्तर में सुधार दर्शाने वाले ब्लॉकों की संख्या
गुजरात	36	13
हरियाणा	36	14
कर्नाटक	41	20
मध्य प्रदेश	9	4
महाराष्ट्र	43	14
राजस्थान	38	13
उत्तर प्रदेश	26	5
कुल योग	**229**	**83**

*****